



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1485]

No. 1485]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2102(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मेघालय के अचिक नेशनल वालटीयर काउन्सिल (एएनवीसी) तथा हनीवट्रैप नेशनल लिबरेशन काउन्सिल (एचएनएलसी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति और एस रबीन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में एक 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/49/2006-एनई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2006

S.O. 2102(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice S. Ravindra Bhat, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as Unlawful Association.

[F. No. 11011/49/2006-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.